राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 04 जून 2026
वर्ष 14, अंक 55, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

यूपी में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और होगी मजबूत, जल्द जारी होगा सोशल सिक्योरिटी कोड...03

अधिवक्ता हितों की प्रभावी पैरवी से चैंबर आवंटन की दरों एवं सुरक्षा निधि में ऐतिहासिक संशोधन...04

शादीशुदा बेटी भी रोजगार की पात्र... अनुकंपा नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

● सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता पर आश्रित विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के पात्र माना है. इससे पहले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता पर आश्रित विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के पात्र माना है. एससी ने फैसले में कहा है कि माता-पिता के ना रहने पर उनपर आश्रित विवाहित पुत्री अनुकंपा रोजगार की पात्र है. अगर विवाहिता बेटी रोजगार संबंधी सभी शर्तों को पूरा करती हैं तो उन्हें नियुक्ति के पात्र माना जाएगा. इससे पहले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को रद्द किया है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के उन सभी निर्णयों से सहमत है, जिनमें कहा गया है कि वैवाहिक स्थिति किसी पात्र पुत्री को कल्याणकारी योजना से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती. यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच द्वारा सर्वोच्च अदालत को भेजे गए एक संदर्भ से संबंधित है, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या विवाहित पुत्रों के मामले में ऐसी कोई अक्षमता न होने पर भी विवाहित पुत्रियों के अनुकंपा नियुक्ति के दावों को अस्वीकार किया जा सकता है.

दुकान चलाने के लाइसेंस के लिए याचिका की थी दायर

इस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक विवाहित पुत्री है. उसने अनुकंपा के आधार पर उचित दुकान चलाने के लाइसेंस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें विवाहित पुत्रियों को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखा गया था. दरअसल विवाहित होने के बावजूद वह अपने परिवार के साथ रहती थी. एक विकलांग बहन की देखभाल करती थी और अपनी मां के साथ दुकान चलाती थी. अपनी मां के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

पहले के कुछ निर्णयों पर किया गया विचार

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अदालत के समक्ष मौजूद पूर्व निर्णयों पर विचार किया. उन्होंने विमल श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) मामले में खंडपीठ के फैसले पर गौर किया, जिसमें सेवा संबंधी मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 'परिवार' की परिभाषा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के एक समान प्रावधान की व्याख्या करते हुए यह माना गया था कि विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना असंवैधानिक है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और इस प्रकार परिवार की परिभाषा में प्रयुक्त 'अविवाहित' शब्द को निरस्त कर दिया गया था।

इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष कुसुमलता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2021) मामले में विवाहित पुत्री द्वारा चुनौती दिए गए दावे पर 2019 के सरकारी आदेश पर भी विचार किया गया. इसमें यह माना गया कि विमल फैसले का तर्क लागू नहीं किया जा सकता. इसमें यह भी कहा गया कि 2019 के सरकारी आदेश में परिवार की परिभाषा में 'अविवाहित पुत्री' शब्द का प्रयोग भेदभावपूर्ण नहीं है. इसमें यह भी माना गया कि 2019 के सरकारी आदेश की व्याख्या उस तरह से नहीं की जा सकती जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हार्नेस नियमों के प्रावधानों की व्याख्या की थी।

इसी तरह का मत सैदा बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2023) मामले में खंडपीठ द्वारा भी व्यक्त किया गया था. न्यायाधीश ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने रंजना मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के विपरीत निर्णयों को रद्द कर दिया।

चार सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस देने का आदेश

आज सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैदा बेगम का मामला सही कानूनी आधार नहीं है. इस मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता विवाह के बाद भी उसी गांव में रहती रही और उचित मूल्य की दुकान चलाने में अपनी मां की सक्रिय रूप से सहायता करती रही. अपनी मां के निधन के बाद अपीलकर्ता ने अपनी बहन, जो शारीरिक रूप से अक्षम थीं, उनकी जिम्मेदारी संभाली।

विवाहित पुत्री होने के आधार पर उसका आवेदन खारिज करना संवैधानिक रूप से अमान्य है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे लाइसेंस देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया और सक्षम अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

फ्रीज संपत्ति की कीमतों की रक्षा भी जरूरी...हरि शंकर तिबरेवाल केस में छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला

● कानूनी क्षेत्र में इस फैसले को एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है.

● माना जा रहा है कि यह आदेश भविष्य में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत फ्रीज़ की गई प्रतिभूतियों और बड़े निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े मामलों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाजार आधारित संपत्तियों के मूल्य संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने साफ किया है किसी भी फ्रीज की गई निवेशित संपत्ति को केवल सुरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसके आर्थिक मूल्य की रक्षा करना भी जरूरी है।

यह मामला करीब 423 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियों और निवेशों से जुड़ा है जो ड्रीम अचीवर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा.लि., डिस्कवरी बिल्डकॉन प्रा.लि., फॉरेस्ट विनकॉम प्रा.लि., ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट्स कंसल्टेंट प्रा.लि., एबिलिटी वेंचर्स प्रा.लि., एबिलिटी स्मार्टेक प्रा.लि., एबिलिटी गेम्स लिमिटेड और सवर्ण भूमि वाणिज्य प्रा.लि. के पास हैं।

बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम पर ध्यान

हाईकोर्ट ने बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनियों को यह अनुमति दी है कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें. कोर्ट ने माना कि सूचीबद्ध शेयरों और बाजार आधारित निवेशों को अनिश्चितकाल तक फ्रीज़ रखे जाने की स्थिति में उनके मूल्य पर बाजार की अस्थिरता का प्रभाव पड़ सकता है. इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने लंबित कार्यवाही के दौरान भी संपत्तियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा को महत्व दिया है।

हरि शंकर तिबरेवाल से जुड़ा मामला क्या है?

यह मामला उद्योगपति हरि शंकर तिबरेवाल से जुड़े होने के कारण भी विशेष चर्चा में है. हालांकि मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरणों द्वारा लिया जाना अभी शेष है, लेकिन हाईकोर्ट की यह टिप्पणी निवेशित संपत्तियों के संरक्षण के प्रति एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

423 करोड़ के निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट का दृष्टिकोण एसेट वैल्यू प्रोटेक्शन की अवधारणा को नई मजबूती प्रदान करता है. आदेश यह संकेत देता है कि लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान संपत्तियों के वास्तविक आर्थिक मूल्य को सुरक्षित रखने के उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

आर्थिक मोर्चे पर कोर्ट का न्यायिक संतुलन

कोर्ट का यह दृष्टिकोण न्यायिक संतुलन, आर्थिक व्यावहारिकता और संपत्तियों के मूल्य संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे यह संदेश भी जाता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनके आर्थिक मूल्य की रक्षा भी समान रूप से आवश्यक है।

न्यायिक संतुलन और आर्थिक व्यावहारिकता का उदाहरण

कानूनी जानकारों के अनुसार हाईकोर्ट का यह फैसला न्यायिक संतुलन, आर्थिक व्यावहारिकता और संपत्तियों के संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है. यह आदेश इस बात पर जोर देता है कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके आर्थिक मूल्य की रक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

संक्षिप्त ख़बरें

सुरक्षा का फीड बैक लेने सड़क पर उतरे अलीगढ़ SSP नीरज जादौन, पैदल गश्त कर लोगों से किया संवाद

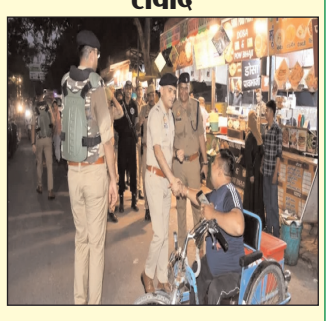

अलीगढ़। जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त किया। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों, प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसएसपी ने शहर में किया पैदल गश्त

पैदल गश्त क्वार्सी चौराहे से किशनपुर तिराहा, गांधीआइ तिराहा, सेंटर प्वाइंट, रेलवे स्टेशन, एसबीआई तिराहा, दीवानी न्यायालय होते हुए पुलिस लाइन तक किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया तथा उन्हें सतर्क और जागरूक रहने की अपील की।

लोगों को सुरक्षा के प्रति किया आश्वत

एसएसपी ने लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे मुख्य मार्गों, चौराहों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार भ्रमणशील रहें तथा संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह भी थे।

नदी की धारा को रोककर लगातार किया जा रहा है अवैध खनन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चोपन /सोनभद्र– सोन नदी के नाम पर पड़ा जिला सोनभद्र की जीवन धारा सोन नदी को ही माना जाता है । बतादें कि सोनभद्र में ही रेणुका, बिजूल,घाघरा ,कनहर आदि अनेक नदियां हैं इन नदियों में अवैध खनन जोर जोर से जारी है। अवैध खनन करने के लिए खनन पट्टाधारक नदी के बीचों बीच मशीनों के द्वारा बालू का उत्खनन किया जा रहा है जहाँ खनन खननकर्ताओं द्वारा नदी की धारा को पूरी तरह से रोक दिया गया है ।मिली जानकारी के अनुसार खनन धारक का पट्टा अगोरी किले के पश्चिम साइड में स्वीकृत हुआ था पर वहां पर खनन तो जारी है लेकिन वहां से हट करके खनन धारक द्वारा नदी के बीचो-बीच प्राचीन शिव मंदिर गोठानी के पास तक खनन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं । जबकि कुछ दूरी पर रूद्रमाइनिंग है जो की लगातार अवैध खनन के कारण सुर्खियों में छाया रहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिले के जिम्मेदार अधिकारी खनन अधिकारी एनजीटी के अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यायवरणविदों/ जानकारों का कहना है कि नदी की धारा रुकने के कारण जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है और वे लगभग विलुप्त होते चले जा रहे हैं। प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश में जलीय जीव जंतुओं के अभ्यारण के लिए जगह को चिन्हित करके उनके रहने और प्रजनन की व्यवस्था कराई जा रही है वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में इन सब नियमों को दरकिनार कर लगातार अवैध खनन जारी है। प्रतिदिन हजारों गाड़ियां ओवर लोड होकर के नदी से निकलती है और उन गाड़ियों में से पानी का रिसाव लगातार जारी रहता है जिससे काला पानी कहे जाने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क को भारी नुकसान हो रहा है । सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होते जा रहे हैं ओवरलोड गाड़ियां चलने की वजह से नदियों पर जो पुल बनाए गए हैं उनकी स्थिति जर्जर होती जा रही है। सड़कों के किनारे पुलों पर बालू के गिर जाने के कारण अगर कोई बाइक सवार उसमें फंस जाता है तो उसकी जान दुर्घटना के कारण जा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं। अधिकारी के कान तक इसकी आवाज तब जाती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुनः इस कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं।क्षेत्र में ओवरलोड गाड़ियों से सड़क तो खराब हो रही है और पुलों पर गाड़ियों से गिरने वाले बालू इकट्ठा हो जा रहे हैं जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और वहीं बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं । स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन को ओवरलोड गाड़ियां क्यों नहीं दिखाई देती हैं । जिसके क्रम में स्थानीय लोगों व पर्यायवरणविदों ने स्थानीय प्रशासन व जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग किया है।

पद बदलते रहे, जिम्मेदारियां बदलती रही लेकिन वैसा ही रहा सुजीत कुमार पाण्डेय का काम करने का अंदाज

» अपनी सादगी और मानवीय व्यवहार के साथ अपराध और अपराधियों के प्रति सत रुख के लिए अलग पहचान रखते हैं डीजी अग्निशमन सुजीत कुमार पाण्डेय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। अपनी सादगी और मानवीय व्यवहार के साथ ही अपराध और अपराधियों के सख्त रुख के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत कुमार पाण्डेय के पास पद कोई भी भी हो पर वे अपनी कार्यकुशलता से हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा उनके कार्यालय में उस वक्त देखने को मिला जब दूरदराज से आये फरियादियों को उन्होंने प्राथमिकता से सुना और उनकी समस्या का निराकरण भी किया। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक अग्निशमन का दायित्व संभाल रहे आईपीएस सुजीत कुमार पाण्डेय के स्वभाव से हर कोई वाकिफ हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बेहद ईमानदारी और कर्मठता के साथ विभाग की सेवा की है।

दिन मंगलवार समय अपराह्न 2 बजे..... साहब ने अपने स्टाफ से पूछा कोई मिलना तो नहीं चाहता, उन्हें लाना। एक बेटी अपने पिता जसपाल सिंह को व्हील चेयर से लेकर डीजी साहब के कमरे में प्रवेश किया।

सुजीत पांडे: क्या हुआ बेटा:

बेटी: सर मेरे पिताजी व्हील चेयर पर है और रामपुर से समय खत्म हो गया है उनका स्थानांतरण लखनऊ हुआ है ये अकेले इतनी दूर इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है कृपया इनका स्थान्तरण निरस्त कर दीजिए।

डीजी साहब: हो जायेगा बेटा। समस्या भी जटिल थी लेकिन ऐसे अफसर जिनकी वाकई में जितनी तारीफ की जाये कम है। इसके बाद ओम प्रकाश सिंह जो आगरा में तैनात है जो पूरी तरह से पैरालिसिस से पीड़ित है जो अपने परिवार के साथ आए थे, उन्होंने अपना स्थानांतरण फिरोजाबाद करवाने का आग्रह किया। हमेशा परेशानी में क्यों न उनका स्टाफ हो छोटा हो या बड़ा लेकिन उनका नजरिया हमेशा सबके लिए एक सा ही रहता है। आईपीएस सुजीत कुमार पाण्डेय ने अपने सरल स्वभाव मृदभाषी सौम्यता से अपनी अलग पहचान बनाई है। डीजी अग्निशमन सुजीत पांडे का यह कोई आज का ही नहीं बल्कि रोज की दिनचर्या है। जनता हो या उनका स्वयं का स्टाफ सभी की परेशानी सुनकर समस्या का निस्तारण उनकी प्राथमिकता में रहता है। एक एसएफओ ने बताया मैंने ट्रांसफर की ऐसी लिस्ट जो बिल्कुल साफ थी जिसमें न कोई भेदभाव था न जातिवाद पहली बार देखा शायद। उस ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे कर्मचारी थे जो अपने जिलों के फायर स्टेशन में 7 साल से 18 साल से तैनात थे जिनको हटाना मुश्किल था उनको भी हटाने का काम किया गया ऐसी निष्पक्षता शायद ही किसी अधिकारी में देखने को मिलती है।

विद्युत कटौती व लो वोल्टेज से उपभोक्ता परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार नगर पंचायत के आद्या नगर, सुभाष नगर और आजाद नगर मोहल्ले में अनियमित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज से आजिज उपभोक्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है। लो वोल्टेज से जूझ रहे उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। रात में ही लोग उपकेंद्र पर जा धमके और विद्युत आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए कनिष्ठ अभियंता कायम सिंह से बात की। समस्या दूर करने का आश्वासन मिला तब जाकर लोग शांत हुए। इन क्षेत्रों में कई दिनों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। परेशान उपभोक्ताओं ने कई बार बिजली अधिकारियों से इस समस्या को दूर करने की गुहार लगाई लेकिन, अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नगर निवासी आलोक, राजू जायसवाल, सतीश, अजीत मोदनवाल, सुधीर ने बताया कि उसका नगर के मुख्य बाजार में उपकेंद्र से इन वार्डो में लगातार कई दिनों से आमजनता बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रही है। शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की ओर से समस्या को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया गया, इसका खामियाजा यहां की जनता भुगत रही है। भीषण गर्मी में लो वोल्टेज के कारण बिजली उपकरण एसी, कूलर, फ्रिज, मोटर पंप काम करना बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से रात्रि में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती हैं। इन लोगों ने इसके स्थाई समाधान के लिए मांग की है।

लालगंज में खाकी की बड़ी लापरवाही: सिपाही से लेकर दरोगा तक सब नदारद, बंद शटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

● लालगंज पुलिस चौकी का शटर बंद देख भड़की जनता, अब देखना है तेज-तर्रार स्क्कबस्ती क्या करेंगे कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। जिले में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और जनता को 24 घंटे सुरक्षा देने के दावों को धत्ता बताती हुई एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लालगंज पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिसिया मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस चौकी को जनता की सुरक्षा का ठिकाना होना चाहिए था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और मुख्य शटर पूरी तरह बंद है।

सिपाही से लेकर होमगार्ड तक गायब, फरियादी बेहाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, लालगंज पुलिस चौकी पर कागजों में सिपाही, दरोगा और होमगार्ड्स की बकायदा तैनाती है। क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं कंधों पर है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आई। ड्यूटी के मुख्य समय पर भी चौकी परिसर में एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दूर-दराज से अपनी शिकायतें और फरियाद लेकर आए पीड़ित लोग चौकी का बंद शटर देखकर हैरान रह गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा, तो स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे नजारे का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया।

जन सुरक्षा और सरकारी दावों पर उठे गंभीर सवाल

व्यस्त और संवेदनशील माने जाने वाले लालगंज क्षेत्र में इस तरह पूरी पुलिस चौकी का भगवान भरोसे छूट जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर दिनदहाड़े पुलिस चौकी ही बंद रहेगी, तो आम जनता अपराधियों के खौफ के बीच अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी? इस बेफिक्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

अब देखना है तेज-तर्रार पुलिस अधीक्षक क्या करेंगे कार्रवाई?

वीडियो के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। बस्ती जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) अपनी तेज-तर्रार कार्यशैली और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब पूरी क्षेत्र की जनता की निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि इस घोर लापरवाही को लेकर तेज-तर्रार पुलिस अधीक्षक बस्ती दोषियों पर क्या और कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं, ताकि भविष्य में जनता की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो।

क्या नए राजनीतिक युग की शुरुआत करेंगे अन्नामलाई?

तमिलनाडु की राजनीतिक भूमि हमेशा से भारतीय राजनीति के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट और पृथक पहचान बनाए हुए है। देश के अन्य राज्यों के विपरीत यहाँ राष्ट्रीय विचारधारा वाले दलों की तुलना में क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय संगठनों का प्रभाव कहीं अधिक गहरा रहा है। बीते अनेक दशकों से द्रविड़ आंदोलन की कोख से निकली राजनीति ने ही इस राज्य की सत्ता की दिशा और दशा को पूरी तरह नियंत्रित और संचालित किया है। ऐसे सुदृढ़ और पारंपरिक राजनीतिक परिवेश में जब कोई नया चेहरा अत्यंत तीव्रता के साथ उभरता है, तो उसकी छोटी से छोटी गतिविधि भी राजनीतिक गलियारों में गहरी हलचल और विमर्श का कारण बन जाती है। इस समय तमिलनाडु के राजनीतिक आकाश में जिस एक नाम को लेकर सबसे अधिक चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं, वे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई। पिछले कुछ समय से राज्य के समाचारों और राजनीतिक चर्चाओं में इस बात ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया है कि वे अपने वर्तमान दल से नाता तोड़कर एक नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई आधिकारिक या स्पष्ट घोषणा नहीं की है, परंतु उनके हालिया वक्तव्य, उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए विज्ञापन पत्र, महत्वपूर्ण बैठकों से उनकी दूरी और जमीनी स्तर पर चल रही संगठनात्मक गतिविधियों ने राज्य की राजनीति को एक नए विमर्श की ओर मोड़ दिया है। इस नए राजनीतिक घटनाक्रम की सुगबुगाहट तब और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी जब कोयंबटूर शहर में अचानक कई प्रमुख स्थानों पर उनके समर्थकों द्वारा बड़े-बड़े विज्ञापन पत्र लगाए गए। सामान्य राजनीतिक विज्ञापनों से सर्वथा भिन्न इन पत्रों पर अंकित संदेश ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें लिखा था कि निडर सोच की कोई सीमा नहीं होती। इस वाक्य को राजनीतिक विश्लेषकों और जनता द्वारा एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा गया। इसके तुरंत बाद जनसंचार के आधुनिक माध्यमों और मुख्यधारा की राजनीति में यह बात तेजी से फैल गई कि वे किसी नए और स्वतंत्र राजनीतिक मंच की आधारशिला रखने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस संभावित कदम को तब और बल मिला जब उनके प्रशंसकों और समर्थकों के संगठन, जिसका नाम अन्नामलाई अन्बू कूट्टम है, उसने अचानक अपनी गतिविधियों को तेज करते हुए नए सदस्यों और पदाधिकारियों को जोड़ना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही भीतरखाने से यह समाचार भी आ रहे हैं कि मक्कल शक्ति इयक्कम नाम से एक विशाल जनआंदोलन या सामाजिक संगठन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो आने वाले समय में एक पूर्ण राजनीतिक दल का रूप धारण कर सकता है। के. अन्नामलाई की पूर्व पृष्ठभूमि और उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा भी अत्यंत रोचक और असाधारण रही है। वे भारतीय पुलिस सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अपनी कर्तव्यनिष्ठ तथा सख्त छवि के कारण वे आम जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए थे। अपनी सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति के मैदान में उतरने के बाद उन्होंने अपने दल को तमिलनाडु में एक नई ऊर्जा और आक्रामकता प्रदान करने का अथक प्रयास किया। उनकी इसी कार्यशैली को देखते हुए वर्ष 2021 में उन्हें तमिलनाडु में दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बहुत ही अल्प समय में वे राज्य की राजनीति का एक अपरिहार्य और चर्चित चेहरा बनकर उभरे। उनकी संवाद शैली अत्यंत सीधी और सीधे प्रहार करने वाली रही है, जिसके कारण उन्होंने वर्तमान द्रमुक सरकार की नीतियों पर लगातार तीखे हमले किए और अपने दल को राज्य में एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में यद्यपि उनका दल राज्य में कोई भी निर्वाचन क्षेत्र जीतने में सफल नहीं हो सका, परंतु उनके नेतृत्व में दल का मत प्रतिशत पहली बार दो अंकों तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिसे राज्य की राजनीति में एक बड़ी घटना माना गया। इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से उनकी जनसभाओं और उनके द्वारा आयोजित की गई एन मन्न, एन मक्कल नामक व्यापक यात्रा को दिया गया, जिसने उन्हें युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया।

परंतु इस तीव्र गति से मिलती सफलता के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी गहरे होते चले गए। उनकी कई आक्रामक टिप्पणियों के कारण उनके दल और उसकी पुरानी सहयोगी संगठन अन्नाद्रमुक के बीच के पारंपरिक संबंध पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने द्रविड़ राजनीति के स्तंभ माने जाने वाले पूर्व नेताओं जैसे अन्नादुरई और जयललिता पर कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन्हें अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने नेताओं का घोर अपमान माना। इसके परिणामस्वरूप दोनों दलों के बीच कटुता इस सीमा तक बढ़ गई कि उनका गठबंधन टूट गया। राजनीतिक क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भविष्य के गठबंधनों को बचाने और राजनीतिक संतुलन बहाल करने के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में वर्ष 2025 में उनके स्थान पर नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु में दल की कमान सौंपी गई। पद से हटाए जाने के बाद भी उनके प्रति निष्ठा रखने वाले समर्थकों और युवाओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनके समर्थकों ने इसे उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता के एक नए अध्याय के रूप में देखा। यही कारण है कि जब हाल के दिनों में उन्होंने दल की दो अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य केंद्रीय समिति की बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, तो उनके अलग रास्ते पर जाने की अटकलों को अत्यधिक हवा मिली।

हाल ही में जब वे चेन्नई हवाई अड्डे से देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उपस्थित संवाददाताओं ने उनसे एक नए दल के गठन की संभावनाओं पर सीधा प्रश्न पूछा। इस पर उन्होंने इस संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया, बल्कि रहस्यमयी ढंग से यह कहा कि वे आगामी 2 दिनों में इस विषय पर बैठकर विस्तार से बात करेंगे। राजनीति की भाषा में किसी भी संभावना से पूरी तरह इनकार न करना इस बात का प्रमाण माना जाता है कि पृष्ठभूमि में कोई बड़ा वैचारिक मंथन चल रहा है। इस वक्तव्य के अतिरिक्त उनके इस नए रास्ते के चयन के पीछे केंद्र सरकार की नई भाषा नीति का विवाद भी एक बहुत बड़ा और तात्कालिक कारण बनकर उभरा है। पिछले ही सप्ताह उन्होंने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना का प्रखर विरोध किया जिसमें कक्षा 9 से तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इतनी अल्प अवधि में विद्यार्थियों पर नई भाषा का बोझ डालना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तमिलनाडु की धरती पर भाषा का प्रश्न हमेशा से ही अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रहा है, जहाँ वर्ष 1960 के दशक में हुए विशाल हिंदी विरोधी आंदोलनों ने राज्य की पूरी राजनीतिक सत्ता को पलट कर रख दिया था। ऐसे संवेदनशील माहौल में अपने ही दल की केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध खड़े होना यह साफ दर्शाता है कि वे अब तमिल पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वर्तमान समय में तमिलनाडु की राजनीति एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है जहाँ द्रमुक सत्तासीन है, परंतु विपक्ष बिखराव की स्थिति में है। अन्नाद्रमुक अपने पुराने वैभव और संगठनात्मक शक्ति को खोती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी ओर प्रसिद्ध अभिनेता विजय का नया दल अपने शानदार चुनावी प्रदर्शन के कारण युवाओं के बीच तेजी से मुख्य विकल्प के रूप में उभर रहा है। ऐसे बहुकोणीय और अस्थिर माहौल में यदि के. अन्नामलाई एक नए राजनीतिक दल के रूप में कदम रखते हैं, तो राज्य के सभी चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। उनके पास आधुनिक सूचना तंत्रों और धरातल पर शिक्षित मध्यमवर्ग तथा युवाओं का एक बहुत बड़ा और निष्ठावान आधार है, जो पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से इतर एक साफ-सुथरी, प्रशासनिक और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का विकल्प चाहते हैं। यद्यपि तमिलनाडु जैसे सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचे वाले राज्य में बिना किसी मजबूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नया दल बनाना और उसे स्थापित करना कोई सुगम कार्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही अनेक छोटे-बड़े क्षेत्रीय दल अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ऐसी स्थिति में विश्लेषकों का अनुमान है कि वे सीधे दल बनाने के बजाय पहले एक व्यापक जनआंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं जो अंततः एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दल का स्वरूप ले सके। उनके इस कदम का सबसे बड़ा आघात उनके पुराने दल पर लगेगा जिसने उनके चेहरे के बल पर राज्य में अपना विस्तार किया था। आने वाले कुछ दिन निश्चित रूप से इस बात का निर्धारण करेंगे कि तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य किस करवट बैठने वाला है।

महेन्द्र तिवारी

अब यूपी में पूर्णकालिक डीजीपी

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश को आखिरकार अपना पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिल गया है। योगी सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। पूर्णकालिक डीजीपी मिलने में उत्तर प्रदेश को चार वर्ष लग गए। इसी के साथ 4 साल बाद कार्यवाहक दौर खत्म हो गया है। मई 2022 में तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटाए जाने के बाद से यूपी पुलिस लगातार कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे चल रही थी। इस दौरान डॉ. डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार और राजीव कृष्ण ने कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली। 31 मई 2025 को प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। अब सरकार ने उन्हें कार्यवाहक के तमगे से मुक्त कर पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंप दी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने डीजीपी नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को 30 साल की सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा था। 26 मई 2026 को यूपीएससी की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी शामिल हुए। पैनल में 1990 बैच की रेणुका मिश्रा, 1991 बैच के पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण के नाम थे। अंततः राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने रविवार को नियुक्ति का शासनादेश जारी किया। राजीव कृष्ण का कार्यकाल जून 2029 तक रहेगा। यूपीएससी की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत वे कम से कम 2 साल तक डीजीपी पद पर रहेंगे। नियुक्ति के बाद राजीव कृष्ण ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की, जहां सीएम ने उन्हें बधाई दी। यूपी पुलिस देश की सबसे बड़ी फोर्स है, जिसमें ढाई लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। डीजीपी का पद सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, खुफिया समन्वय और बड़े आयोजनों की सुरक्षा से जुड़ा रणनीतिक पद है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि बार-बार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करना पुलिस सुधारों की भावना के खिलाफ है। अदालत का मानना है कि पुलिस प्रमुख को निश्चित कार्यकाल और संस्थागत स्थिरता मिलनी चाहिए। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस हैं और 2029 में सेवानिवृत्त होंगे। उनकी नियुक्ति के साथ 2022 से चला आ रहा पूर्णकालिक डीजीपी का इंतजार खत्म हो गया है।

पूर्णकालिक डीजीपी से प्रदेश को काफी फायदे होते हैं। कार्यवाहक डीजीपी का कार्यकाल तय नहीं होता, वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। इससे पुलिस सिस्टम में लंबी अवधि की प्लानिंग नहीं हो पाती। पूर्णकालिक डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कम से कम 2 साल का निश्चित कार्यकाल मिलता है। इससे वो बिना डर के फैसले ले पाता है और काम का सीधा जिम्मेदार भी होता है। कानून-व्यवस्था, पुलिस ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, थानों का आधुनिकीकरण जैसे काम 3-6 महीने में नहीं होते। एक फुलटाइम डीजीपी अपनी विजन के हिसाब से 2-3 साल का रोडमैप बना सकता है और उसे लागू कर सकता है। यूपी में 2022 से 2026 तक लगातार कार्यवाहक डीजीपी बदलने से ऐसे प्रोजेक्ट रुकते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के प्रकाश सिंह केस में कहा था कि बार-बार कार्यवाहक नियुक्ति से पुलिस की स्वायत्तता खत्म होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। पूर्णकालिक डीजीपी का चयन यूपीएससी के पैनल से होता है, जिससे चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और मेरिट बेस्ड होती है। ढाई लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों वाली यूपी पुलिस में सबसे ऊपर अगर स्थायी मुखिया बैठे हों तो नीचे तक मैसेज साफ जाता है। कार्यवाहक डीजीपी के दौर में अफसरों में ये असमंजस रहता है कि उनके आदेश कितने लंबे चलेंगे। इससे फील्ड लेवल पर फैसला लेने में हिचक होती है। कुंभ, चुनाव, कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में पुलिस की भूमिका सबसे अहम होती है। एक फुलटाइम डीजीपी के पास समय होता है कि वो पहले से प्लानिंग करे, इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन करे और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बैठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकारें बार-बार कार्यवाहक डीजीपी न लगाएं। ये पुलिस रिफॉर्म्स के खिलाफ है। यूपी को 4 साल बाद पूर्णकालिक डीजीपी मिलना इसी कानूनी बाध्यता को पूरा करना भी है। हालांकि इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि राजीव कृष्ण को ही पूर्णकालिक डीजीपी बनाया जा सकता है लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा रविवार को हुई।

धरती को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है - खेत बचाओ अभियान

भारत में सरकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उनकी शुरुआत प्रायः अभियानों के माध्यम से की जाती है। निश्चित रूप से जिन अभियानों का उद्देश्य पवित्र और जनहितकारी होता है, वे सफल भी होते हैं। देश को गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने के लिए पल्स पोलियो, चेचक उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण, स्वच्छ भारत अभियान और एड्स निवारण जैसे अनेक राष्ट्रीय अभियान चलाए गए। इन अभियानों को शासकीय अमले ने ईमानदारी से जमीनी स्तर पर लागू किया और मैदानी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की अथक मेहनत से देश कई गंभीर चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सका। यह इन अभियानों की सार्थकता का प्रमाण है। खेती की उन्नति और किसानों के हित में देश में अनेक योजनाएं बनाई गईं, लेकिन खेतों को बचाने के लिए किसी व्यापक जन अभियान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यदि आज भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 'खेत बचाओ अभियान' चलाया जा रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि बेटियों की तरह खेतों का अस्तित्व भी संकट के दौर से गुजर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कृषि मंत्री का दायित्व संभालने के बाद से शिवराज सिंह चौहान अपनी सहज, आत्मीय और जनसंपर्क आधारित कार्यशैली के कारण सीधे किसानों से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बाद यदि किसी केंद्रीय मंत्री का नाम आम लोगों की जुबान पर सबसे अधिक सुनाई देता है, तो उसके पीछे किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी समस्याओं के समाधान की निरंतर कोशिशें हैं। वे देशभर में किसानों के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलते हैं और उनके हित में नीतिगत उपाय खोजते हैं। वैश्विक परिदृश्य भी खेती के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय तनाव और ऊर्जा संकट के कारण रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता तथा लागत पर दबाव बढ़ रहा है। इसका सीधा असर किसानों की उत्पादन लागत और उपज दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसानों को इन चुनौतियों से बचाने तथा खेती को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी देशभर में सराहना हो रही है।

अधिक उत्पादन की चाह में पिछले कई दशकों से देश के अधिकांश किसान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते रहे हैं। प्रारंभिक वर्षों में इन उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाने में मदद की, लेकिन धीरे धीरे इनके दुष्परिणाम सामने आने लगे। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम होती गई, जैविक तत्व नष्ट होने लगे और खेती की लागत लगातार बढ़ती चली गई। परिणामस्वरूप आज अनेक किसानों के लिए रासायनिक खेती लाभ के बजाय घाटे का सौदा बनती जा रही है। इसी कारण कई किसान पारंपरिक खेती से दूरी बनाकर अपनी कृषि भूमि को उद्योगों, गोदामों अथवा आवासीय कॉलोनियों के लिए बेचने को मजबूर हो रहे हैं। यह केवल किसान का संकट नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार का यह अभियान धरती को पुनः जीवंत बनाने और मिट्टी में प्राकृतिक पोषक तत्वों की पुनर्स्थापना का प्रयास है। खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को देसी खाद, जैविक संसाधनों और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि खेती को पुनः हरा भरा, लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। शिवराज सिंह चौहान देशभर के किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि वे मिट्टी की सेहत को नष्ट करने वाले रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें और जैविक विकल्पों को अपनाएँ। यह अभियान केवल भारत सरकार या कृषि मंत्री का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अभियान है। आखिरकार देश की हर थाली में पहुँचने वाला अन्न किसान के खेतों से ही आता है। हम चाहे कितने भी आधुनिक, तकनीकी और स्मार्ट क्यों न हो जाएँ, पेट की भूख आज भी रोटी से ही शांत होती है। निस्संदेह खेती को उन्नत बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन यदि विकास की दौड़ में खेतों की मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो दे और भूमि बंजर होने लगे, तो यह प्रगति नहीं, विनाश का संकेत होगा। इसलिए देश के किसानों और खेतों को इस संकट से बचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आइए, हम सभी धरती को जीवंत रखने के इस पवित्र महाअभियान का हिस्सा बनें और खेत बचाओ अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हरा भरा, समृद्ध और खुशहाल भारत विरासत में मिल सके।

अरविंद रावल

कविता

कई चेहरे नक़ाबों में संवरने लगे।

खुले आकाश में परिंदे मंडराने लगे हैं,
दूसरे पंछियों को वो बहकाने लगे हैं।

कल तक नहीं जिन्हें गलियों का ज्ञान
वही अब राह सबको दिखाने लगे हैं।

ज़रा-सी धूप क्या मिली कामयाबी की,
अपनीं परछाइयां से भी कतराने लगे हैं।

जो दर्द में शामिल थे हर इक मोड़ पर,
मस्ती की भीड़ में तेवर दिखाने लगे हैं।

ये बहकी हवाओं का असर आजकल,
फूलों के बीच काँटे भी इतराने लगे हैं।

हुनर कम और शोर का आलम ज्यादा,
ख़ाली बर्तन भी अब टकराने लगे हैं।

फरेबी आँधियों ने सच को ढक दिया,
आईने झूठ की सूरत सँवारने लगे हैं।

मजबूती से पांव रख अपनी ज़मीं पर
जो ऊँचे उड़ उड़े, अब खबराने लगे हैं।

नज़र रखना समय के मिज़ाज संजीव,
कई चेहरे नक़ाबों में संवरने लगे।

संजीव ठाकुर

दैनिक राशिफल

मेष आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। **शुभ रंगः** लाल 7 **शुभ अंकः** 9

वृषभ रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। **शुभ रंगः** सफेद 7 **शुभ अंकः** 6

मिथुन आज व्यस्तता अधिक रहेगी। कार्यों में सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। यात्रा के योग बन सकते हैं। **शुभ रंगः** हरा 7 **शुभ अंकः** 5

कर्क परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। **शुभ रंगः** चांदी 7 **शुभ अंकः** 2

सिंह नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंगः सुनहरा 7 शुभ अंकः 1

कन्या आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। व्यापार में नई योजनाएं लाभदायक रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। **शुभ रंगः** हरा 7 **शुभ अंकः** 7

तुला भाग्य का साथ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामलों में संतुलित व्यवहार रखें। निवेश के लिए दिन अच्छा है।
शुभ रंगः गुलाबी 7 **शुभ अंकः** 6

वृश्चिक कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंगः मैरून 7 **शुभ अंकः** 8

धनु धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। करियर में प्रगति के संकेत हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है।
शुभ रंगः पीला 7 **शुभ अंकः** 3

मकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। **शुभ रंगः** नीला 7 **शुभ अंकः** 4

कुंभ साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
शुभ रंगः आसमानी 7 **शुभ अंकः** 11

मीन नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
शुभ रंगः पीला 7 **शुभ अंकः** 7

पेपर लीक की आड़ में डिजिटल शिक्षा पर अंजना का 'दो कौड़ी' तंज

[दो कौड़ी कहने वाली जुबान और करोड़ों भाग्य बदलने वाले हाथ]

[अंजना की टिप्पणी या शिक्षा पर चोट? यूट्यूब टीचर्स क्यों बने मुद्दा]

भारतीय शिक्षा जगत में यह शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो कि एक टीवी स्टूडियो में कही गई टिप्पणी इतनी तेज़ी से राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाए। लेकिन जब वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप ने नीट पेपर लीक पर चर्चा के दौरान यूट्यूब शिक्षकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानते कुछ नहीं' और उन्हें 'दो कौड़ी के यूट्यूब गुरु' तक कह दिया, तो यह सिर्फ एक टीवी बहस नहीं रही। यह बयान देखते ही देखते 'ब्लैकबोर्ड पर ब्रेकिंग न्यूज़' बन गया। वास्तव में, यह डिजिटल शिक्षा की बढ़ती ताकत के सामने मुख्यधारा मीडिया की असहजता को उजागर करता है। अंजना का यह हमला तथ्यों से अधिक पूर्वाग्रह का प्रतीक प्रतीत होता है। जब लाखों छात्रों का भरोसा किसी मंच से जुड़ जाए, तो उस पर उठी उंगली केवल व्यक्तियों पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर सवाल बन जाती है। अंजना ओम कश्यप की इस टिप्पणी को खान सर, अभिनय शर्मा जैसे लोकप्रिय यूट्यूब शिक्षकों पर भी लागू माना गया। उन्होंने कुछ डिजिटल शिक्षकों को 'बड़ा फ्रॉड' तक कह दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब लाखों छात्र ऑनलाइन शिक्षा के सहारे अपने सपने संवार रहे हैं। इसलिए इसे केवल कुछ शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल शिक्षा जगत की साख पर प्रहार माना गया। सवाल है, क्या यह आलोचना तथ्यों पर आधारित है या महज़ सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश? क्या कुछ अपवादों के आधार पर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित है? शोर और आरोपों से परे, किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन उसके परिणामों से होता है। पिछले एक दशक में यूट्यूब आधारित शिक्षा ने लाखों छात्रों तक ज्ञान पहुँचाया, जिनकी पहुँच महंगी कोचिंग तक नहीं थी। खान सर और अभिनय शर्मा जैसे शिक्षकों ने दूर-दराज़ क्षेत्रों के युवाओं को अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास दिया। इनके पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण लाखों सफल छात्र हैं। यदि ये 'कुछ नहीं जानते ', तो यह सफलता कैसे संभव हुई? हालाँकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उनसे पूरे योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अंजना जी, यह आरोप केवल शिक्षकों पर नहीं, उनके समर्पण और मेहनत पर भी सवाल उठाता है।

जब दुनिया थम-सी गई थी और शिक्षा के पारंपरिक रास्ते बंद हो गए थे, तब डिजिटल मंचों ने सीखने की लौ बुझने नहीं दी। कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षक लाखों विद्यार्थियों के लिए सहारा बने। स्कूलों और कक्षाओं के बंद रहने पर मोबाइल और इंटरनेट के जरिए शिक्षा घर-घर पहुँची। जहाँ कई कोचिंग संस्थानों की फीस लाखों रुपये तक है, वहीं अनेक यूट्यूब शिक्षक मुफ्त या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को सीमित दायरों से निकालकर आम लोगों तक पहुँचाया है। ऐसे योगदान को अनदेखा कर पूरे समुदाय को फ्रॉड बताना न केवल अनुचित, बल्कि एकतरफा दृष्टिकोण भी है। हालाँकि कुछ चैनलों में क्लिकबेट, भ्रामक थंबनेल और पेड कोर्स की आक्रामक मार्केटिंग जैसी समस्याएँ भी मौजूद हैं।

विवाद के बीच शिक्षकों की प्रतिक्रिया ने अंजना के आरोपों पर नए सवाल खड़े कर दिए। अभिनय सर और खान सर जैसे शिक्षकों ने कहा कि उनका काम छात्रों का भविष्य संवारना है, न कि सनसनी फैलाना। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई उन्हें ज्ञानहीन सिद्ध कर दे, तो वे सीखने को तैयार हैं, लेकिन निराधार आरोप स्वीकार्य नहीं हैं। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर छात्रों ने भी खुलकर उनका समर्थन किया। हजारों प्रतिक्रियाओं में छात्रों ने बताया कि इन शिक्षकों ने शिक्षा को महंगे दायरों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया है। ऐसे में 'दो कौड़ी' जैसी टिप्पणी केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों और परिवारों के विश्वास पर भी चोट करती है, जो उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। इस प्रकरण ने मुख्यधारा मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। जब यूट्यूब शिक्षक नीट लीक, सीबीएसई विवादों और शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर आवाज उठाते हैं, तो उन्हें फ्रॉड कहकर खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या टीवी एंकर हर विषय के अंतिम विशेषज्ञ हैं? यदि डिजिटल मंचों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाता है, तो टीआरपी-केंद्रित बहसों की निष्पक्षता भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप का बयान इसी विरोधाभास को उजागर करता है। एक ओर डिजिटल शिक्षक शिक्षा की पहुंच बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके योगदान पर संदेह जताया जा रहा है।

डिजिटल शिक्षा जगत भी कमियों से पूरी तरह अछूता नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनलों पर क्लिकबेट और भ्रामक जानकारी की समस्या मौजूद है, जिसकी आलोचना और जवाबदेही आवश्यक है। कुछ टीचर्स पर पेपर लीक या गलत मार्गदर्शन के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन कुछ उदाहरणों के आधार पर पूरे समुदाय को 'फ्रॉड' या 'दो कौड़ी का' कहना उचित नहीं। शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है, पर उसके नाम पर पूरे आंदोलन को अपमानित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन तथ्यों और परिणामों से होना चाहिए, न कि अपमानजनक टिप्पणियों से। अंजना का बयान इसी अतिसामान्यीकरण की मिसाल प्रतीत होता है।

वस्तुतः, इस पूरे विवाद का केंद्र कोई एंकर या शिक्षक नहीं, बल्कि शिक्षा का बदलता परिदृश्य है। आज करोड़ों छात्र सीमित संसाधनों के बीच डिजिटल मंचों के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यधारा मीडिया और डिजिटल शिक्षा जगत, दोनों से संतुलन, जवाबदेही और संवाद की अपेक्षा है। किसी शिक्षक का मूल्यांकन आरोपों या उपहास से नहीं, बल्कि उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होना चाहिए। 'दो कौड़ी के गुरु' जैसी टिप्पणी केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि उन करोड़ों छात्रों के विश्वास और आकांक्षाओं पर भी आघात है; ऐसे में संबंधित टिप्पणी पर पुनर्विचार और खेद की अपेक्षा स्वाभाविक है। शिक्षा राष्ट्र की नींव है; इसलिए इस पर विमर्श पूर्वाग्रह नहीं, तथ्यों और सम्मान के आधार पर होना चाहिए।

प्रो.आरके जैन 'अरिजीत'

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

बालाजी मंदिर पर भंडारे में सम्मिलित हुए ब्लाक प्रमुख

बरेली/विकासखंड भदपुरा के ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रताप गंगवार समेत मेथी चौराहा स्थित बालाजी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी भव्य भंडारी का आयोजन किया गया। यह मंदिर नवाबगंज पीलीभीत के बरखेड़ा मार्ग पर स्थित पुरैनिया जाने वाले चौराहे पर स्थित है यहां पर प्रत्येक वर्ष भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है इस भंडारे में क्षेत्र के लोगों के साथ इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों के लिए भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था की गई । जिसके लिए सड़क के किनारे भोजन की व्यवस्था की गई साथ ही मंदिर पर भंडारे में पहुंचने वाले व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी जिसके तहत भंडारे में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की सुविधा न हो सके इस भंडारे में भदपुरा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार पहुंची यहां पहुंचने पर लोगों ने उनका अब स्वागत किया उनके साथ प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रताप गंगवार अन्य लोग उपस्थित थे

मिश्रिख में बड़े मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

मिश्रिख (सीतापुर)- बड़े मंगल के पावन अवसर पर मिश्रिख तहसील चौराहे पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया तथा बजरंगबली के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भंडारे का आयोजन ग्राम पंचायत आट के प्रधान प्रत्याशी अनुराग मिश्रा पवन पतौजा एवं प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी के नेतृत्व में किया गया। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन एवं प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई थी।आयोजक ने बताया कि बड़े मंगल के अवसर पर सेवा एवं भक्ति की भावना से यह भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द का संदेश भी दिया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं एवं राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजन की सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रही और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

चॉकलेट के पैकेट में छिपाकर लाया गया 13 करोड़ रुपये का गांजा, लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने पकड़ा

लखनऊ। बैंकॉक से बड़े पैमाने पर आ रहे हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) गांजा पकड़े जाने के बाद अब तस्करों ने अपना रूट बदल दिया है। बैंकॉक से तस्करों ने 13 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड की खेप को मस्कट भेजा और वहां से एक करियर के माध्यम से लखनऊ पहुंचाया गया। यहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने चॉकलेट के पैकेट में लिपटे करीब 13 करोड़ रुपये की कीमत के हाइड्रोपोनिक वीड को बरामद कर लिया।

साथ ही एक करियर को भी गिरफ्तार किया गया है। वायुसीमा शुल्क के अपर आयुक्त जितेंद्र सिंह की टीम सोमवार देर रात एयरपोर्ट पर सतर्क थी। इस बीच ओमान एयर का विमान डब्ल्यूवाइ-265 मस्कट से लखनऊ पहुंचा था। कस्टम की टीम यात्रियों के सामान की जांच कर रही थी। चेक-इन बैगेज की एक्स-रे इमेजिंग से जांच की तो उसमें कुछ संदिग्ध वस्तु नजर आयी । यह लगेज लखनऊ के लिए बुक था। टीम ने यात्री का पता लगाया और फिर उसके सामने तलाशी ली। यात्री ने बैग खोला तो उसमें चाकलेट के पांच बड़े पैकेट मिले। हर चाकलेट पैकेट के भीतर दो-दो पालिथीन बैग वीड को छिपाकर रखा गया था। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

यूपी में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और होगी मजबूत, जल्द जारी होगा सोशल सिक्योरिटी कोड

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का बड़ा लाभ देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड की नियमावली इस माह जारी कर सकती है। नियम लागू होने के बाद प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी राशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा। श्रम विभाग की नियमावली के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद इसे अधिसूचित कर लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों का पंजीकरण डिजिटल प्लेटफार्म पर किया जाएगा। राशन कार्ड और श्रमिक पहचान से जुड़े डाटा को विभिन्न राज्यों की प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। इससे प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्य में काम करते हुए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े अस्पतालों में उन्हें इलाज की सुविधा मिलेगी। नियमावली के तहत अनुबंध (फिक्स्ड टर्म) पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। उन्हें सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक ग्रेच्युटी का अधिकार होगा। महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश और मेडिकल बोनस की सुविधा दी जाएगी। वहीं, किसी श्रमिक की छंटनी होने पर उसके पुनर्वास और नए रोजगार के लिए री-स्किलिंग फंड बनाया जाएगा। इसके लिए नियोक्ता को संबंधित कर्मचारी के 15 दिन के वेतन के बराबर राशि फंड में जमा करनी होगी, जिससे उसे नया कौशल प्रशिक्षण मिल सके। नियमावली में पहली बार आनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी पार्टनर, कैब चालक समेत गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने का प्रविधान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रमिकों को रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।

बिजली और नहरों में पानी की मांग को लेकर किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

लालगंज (रायबरेली)। बिजली आपूर्ति और नहरों में पानी की समस्या को लेकर सोमवार को जय किसान जन कल्याण सेवा समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में पदाधिकारी ने बिजली व्यवस्था बहाल करने और नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसडीएम राजेश श्रीवास्तव को ज्ञापन देते हुए कहा कि क्षेत्र की नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। वहीं कई गांवों में नलकूप और हैंडपंप भी पानी नहीं दे रहे हैं। तालाब सूख चुके हैं, जिससे ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से बिजली आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसका खामियाजा किसानों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। समिति ने क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने और नहरों में शीघ्र पानी छोड़े जाने की मांग की है।

दो दशक पुराना काल्हीगांव संपर्क मार्ग बदहाल, बारिश में आवागमन होता है दुश्वार सड़क पर निकले बड़े-बड़े बोल्डर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज(रायबरेली)। क्षेत्र का काल्हीगांव संपर्क मार्ग वर्षो से बदहाली का दंश झेल रहा है।करीब दो दशक पूर्व विधायक निधि से निर्मित यह सड़क आज पूरी तरह जर्जर हो चुकी है,लेकिन इसकी मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की ओर किसी भी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं है।सड़क की खराब स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में मतदान बहिष्कार तक की चेतावनी दे डाली है।ग्रामीणों के अनुसार यह संपर्क मार्ग तत्कालीन विधायक अशोक कुमार सिंह के कार्यकाल में बनाया गया था।निर्माण के बाद से अब तक सड़क की कोई सुध नहीं ली गई।समय के साथ सड़क उखड़ चुकी है और जगह-जगह बड़े-बड़े बोल्डर निकल आए हैं,जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता विकास के बड़े-बड़े वादे करते हैं,लेकिन जीत के बाद क्षेत्र की समस्याओं को भूल जाते हैं।वर्तमान विधायक,सांसद तथा अन्य जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क निर्माण की मांग की गई,लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है।कीचड़ और गड्ढों से भरे मार्ग पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं,लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि तमाशबीन बने हुए हैं। ग्रामीणों कृष्ण कुमार अग्निहोत्री, रजोले शुक्ला, गोवर्धन अग्निहोत्री, विजय शंकर शुक्ला, सधन अग्निहोत्री, मोनू,भोलू, पुतानी, अशोक मिश्रा, गौरव शुक्ला, कमल, लल्लू शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला, पुतानी आदि ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आगामी चुनाव में मतदान बहिष्कार सहित लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग की है।

योगी सरकार में गांवों को मिली नई पहचान, यूपी की 57694 पंचायतों में स्थापित हुए ग्राम सचिवालय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में ग्रामीण विकास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना कर ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पिछले पांच वर्षों में 24,311 पंचायत भवनों का निर्माण कर पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। ग्राम सचिवालयों की स्थापना से ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं की जानकारी, मनरेगा संबंधी सेवाएं, जन्म-मृत्यु पंजीकरण समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब बार-बार तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। पिछले 5 वर्षों में 24,311 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। ग्राम सचिवालयों में फर्नीचर, कम्प्यूटर, इंटरनेट, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की गई है। कुल 1875 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और कन्सल्टिंग इंजीनियर(सिविल) का इम्पैनलमेंट किया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली समस्त धनराशि का भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर से किये जाने के लिए जिओ फेन्स्ड एंड क्यू आर कोड तकनीक (Geo fenced and QR Code technique) लागू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से धनराशि के व्यय में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। एआई मॉडल का प्रयोग कर व्यय का अनुश्रवण किया जा रहा है। समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं संचार हेतु राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर एवं आनलाइन अटेण्डेन्स सिस्टम लागू किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इन भवनों में पंचायत बैठकों, जनसुनवाई, डिजिटल सेवाओं और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पंचायत भवनों के निर्माण से ग्राम पंचायतों को स्थायी कार्यालय मिले हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। ग्राम सचिवालय और पंचायत भवनों का यह व्यापक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को नई गति देने के साथ-साथ गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इससे ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह उपलब्धि प्रदेश के गांवों को सशक्त, डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

भारत स्काउट और गाइड, उ. प्र. द्वारा पांचवें बड़े मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में दिनांक 2 जून, 2026 को भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश जनपद लखनऊ द्वारा जिला संस्था के संपर्क कार्यालय उदयाचल (क्वींस कॉलेज कैंपस) बाला कदर रोड लालबाग, लखनऊ पर पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर विशाल भंडारे तथा जलप्याऊ शिविर का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के सहायक प्रादेशिक आयुक्त एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मंडल लखनऊ डा0 प्रदीप कुमार तथा जिला संस्था के संरक्षक डा0 आर. पी. मिश्र द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व पूजन कर भोग लगाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ0 प्रदीप कुमार ने कहा कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी ज्येष्ठ मास के प्रत्येक बड़े मंगल के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड लखनऊ के तत्वावधान में विभिन्न विद्यालयों द्वारा भंडारे व जलप्याऊ शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो कि एक सराहनीय कार्य है। जिला संस्था द्वारा लखनऊ की संस्कृति से जोड़े रखने के इस प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। जिला सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि भंडारे में मुख्य अतिथि डॉ0 प्रदीप कुमार, जिला संरक्षक डॉक्टर आर पी मिश्र, माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा प्रदेशीय मंत्री डॉ आर के त्रिवेदी, भारत स्काउट और गाइड संस्था के जिला मुख्यायुक्त डॉ0 जेपी मिश्र, जिला उपाध्यक्ष शर्मिला सिंह, जिला सचिव अनिल शर्मा डीओसी (गाइड) मधु हंसपाल आदि द्वारा जनमानस को कढ़ी, चावल, बूंदी व शरबत वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ0 प्रदीप कुमार, जिला संरक्षक डॉ0 आरपी मिश्र, जिला मुख्य आयुक्त डॉ0 जेपी मिश्र, जिला उपाध्यक्ष शर्मिला सिंह, उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रदेशीय मंत्री डॉ0 आरके त्रिवेदी, जिला आयुक्त (गाइड) संगीता अग्रवाल, जिला कमिश्नर (स्काउट) डा0 महेंद्र तिवारी, डीओसी गाइड मधु हंसपाल, जिला कोषाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव डॉ0 मीता श्रीवास्तव, एएसओसी लखनऊ मंडल गरिमा पाल, प्रधानाचार्यगण डॉ0 के मिश्र, अजीत कुमार, आर.के. सिंह के अलावा जनपद के स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकायें उपस्थित रहे।

विवादित ढांचे पर झूठी खबरें चलाने वालों पर भड़के योगेश पासी,'फर्जी रिपोर्टिंग' का आरोप, कार्रवाई की मांग

● SHO ने कहा- नहीं मिली किसी टीम के आने की जानकारी, फिर कैसे छपी खबर?

विवादित ढांचे पर 'फर्जी रिपोर्टिंग' का आरोप, कार्रवाई की मांग

विवादित स्थल पर पुरातत्व टीम के दावे पर सवाल, योगेश पासी ने मांगी जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कलां स्थित विवादित ढांचे को लेकर कुछ समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा यह खबर प्रकाशित की गई कि विवादित स्थल पर पुरातत्व विभाग की दो सदस्यीय टीम पहुंची थी और उसने वहां कब्र एवं मस्जिद होने के प्रमाण मिलने की बात कही है। इस खबर को लेकर सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी ने कड़ा विरोध जताया है और इसे पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन बताया है। योगेश पासी ने कहा कि कुछ तथाकथित पत्रकार और समाचार पत्र बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है। उनका कहना है कि यदि वास्तव में कोई सरकारी अथवा पुरातत्व विभाग की टीम विवादित स्थल पर पहुंची थी, तो इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? टीम के सदस्यों की पहचान क्या थी? उनका कोई फोटो, वीडियो या आधिकारिक बयान अब तक सामने क्यों नहीं आया? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले में यदि किसी जांच टीम ने कोई निष्कर्ष निकाला होता तो प्रशासन या संबंधित विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जनता को जानकारी दी जाती। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, जिससे इन खबरों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक (SHO) सुरेंद्र सिंह भाटी ने भी बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी पुरातत्व विभाग की टीम ने विवादित ढांचे का निरीक्षण किया हो। साहृ के इस बयान के बाद उक्त खबरों को लेकर और भी सवाल उठने लगे हैं। योगेश पासी ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान स्वयं ही फैसला सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मामला अभी भी विवादित है और किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की खबरें समाज में भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही हैं।

सुहेलदेव आर्मी प्रमुख ने कहा कि उनकी टीम पूरे मामले से संबंधित तथ्यों और प्रकाशित खबरों का संकलन कर रही है। जल्द ही संबंधित समाचार पत्रों एवं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रशासन को लिखित शिकायत दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा बिना प्रमाण और बिना

आधिकारिक पुष्टि के संवेदनशील खबरें प्रकाशित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास न कर सके। फिलहाल विवादित ढांचे को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी भी विभाग द्वारा कब्र या मस्जिद होने संबंधी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे केवल प्रशासनिक और आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें तथा अफवाहों से दूर रहें।

भंडसर बैगुल नदी में कट्टा मिलने से गोकशी की उड़ी अफवाह, डॉक्टरों की जांच में निकली भैंस की खाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बरेली। सोमवार देर शाम कस्बे के पास से बहने वाली बैगुल नदी में एक संदिग्ध कट्टा मिलने से सनसनी फैल गई। कट्टे से उठ रही तेज दुर्गंध के कारण इलाके में प्रतिबंधित पशु की गोकशी किए जाने की अफवाह तेजी से फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच एवं स्वाभिमान सुरक्षा समिति के नगर अध्यक्ष तेजपाल सक्सेना , इंद्रपाल सक्सेना, तरूण गुप्ता, अनिल कनौजिया सुरेंद्र गंगवार कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत हाफिजगंज थानाध्यक्ष व रिठौरा चौकी प्रभारी को फोन किया गया। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की। मंगलवार सुबह पशु चिकित्साधिकारी की अगुवाई में पहुंची तीन सदस्यीय टीम ने राहत की सांस दिलाई। हिजामं कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोवंश पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए वे जंगलों में भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। नदी में संदिग्ध कट्टा मिलने की जानकारी पर पुलिस बल भेजा गया था। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, वह भैंस की खाल थी। अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है।संतोष कुमार थानाध्यक्ष, हाफिजगंज।

मंगलवार सुबह डॉक्टरों की टीम ने मौके पर जाकर नदी से बरामद खाल का तकनीकी परीक्षण किया। जांच में वह पूरी तरह भैंस की खाल पाई गई है। सैंपल कलेक्ट कर आवश्यक विधिक रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।

ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल पर क्षेत्र भर में हुए विशाल भंडारों में भक्तों ने चखा प्रसाद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल पर मंगलवार को महराजगंज कस्बे सहित संपूर्ण तहसील क्षेत्र भक्तिरस में सराबोर दिखाई दिया। सुबह से देर शाम तक हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। विधि-विधान से पूजा-अर्चना, सुंदरकांड पाठ, हवन-पूजन और विशाल भंडारों के आयोजन के बीच पूरा क्षेत्र 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' के जयघोष से गूंजता रहा। कस्बे से लेकर ग्रामीण अंचलों तक धार्मिक अनुष्ठानों और सेवा कार्यों की ऐसी छटा देखने को मिली जिसने आस्था, सेवा और सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि, महराजगंज कस्बे के रायबरेली रोड स्थित प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर दानेश्वर धाम, कोतवाली परिसर स्थित हनुमान मंदिर, पुलिस चौकी तिराहा, बछरावां रोड, हैदरगढ़ रोड, चंदापुर रोड तथा इन्हौना रोड समेत अनेक स्थानों पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने बजरंगबली को भोग अर्पित कर पूड़ी, सब्जी, बूंदी, शरबत और ठंडी छाछ का प्रसाद ग्रहण किया। विभिन्न व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आयोजित भंडारों में सभी वर्गों और समुदायों के लोगों की सहभागिता देखने को मिली, जिसने गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। रायबरेली रोड स्थित प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में समाजसेवी सुमित कुमार गुप्ता 'सोथी वाले' के संयोजकत्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रातःकाल विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हनुमान जी का पूजन-अर्चन एवं हवन सम्पन्न कराया गया। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचवटी परिवार के मुखिया गणेश प्रताप सिंह ने भगवान हनुमान के चरणों में मत्था टेककर प्रदेश एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की तथा स्वयं प्रसाद वितरण कर सेवा कार्य में सहभागिता निभाई। गणेश प्रताप सिंह, मुखिया - पंचवटी परिवार ने कहा कि, 'बड़ा मंगल केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। भगवान हनुमान शक्ति, भक्ति और लोककल्याण के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजनों से समाज में प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना मजबूत होती है। ' इस अवसर पर नगर पंचायत की अध्यक्ष सरला साहू, प्रथम नागरिक प्रभात साहू, पूर्व विधायक राजाराम त्यागी, लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी एडवोकेट, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुधा अवस्थी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। महराजगंज कोतवाली परिसर स्थित हनुमान मंदिर में कोतवाल जगदीश यादव के नेतृत्व में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह संगीतबद्ध सुंदरकांड पाठ, हवन-पूजन एवं आरती के बाद विशाल भंडारे का शुभारंभ हुआ। नगर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। जगदीश यादव, प्रभारी निरीक्षक (कोतवाल), महराजगंज ने कहा कि, 'बड़े मंगल के अवसर पर धार्मिक आयोजन एवं भंडारे सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हैं। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है। सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम

शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ' इस मौके पर एसएसआई देवेंद्र भदोरिया, एसआई रोहित कुमार, एसआई रजत वर्मा, एसआई दिनेश गोस्वामी सहित समस्त पुलिस कर्मी एवं महिला आरक्षियां श्रद्धालुओं की सेवा और व्यवस्था में पूरे समर्पण के साथ जुटी रहीं। पुलिस परिवार द्वारा किए गए इस आयोजन की लोगों ने सराहना की। कस्बे के तिराहे पर स्थित पुलिस चौकी परिसर में साईं सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा पांचवें बड़े मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूजा-अर्चना और आरती के उपरांत प्रारंभ हुए भंडारे में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। समिति के सदस्य पूरे दिन सेवा कार्य में लगे रहे और भक्तों को प्रसाद वितरित करते रहे। प्राचीन शिव मंदिर दानेश्वर धाम में वार्ड संख्या-4 शांतिनगर निवासी विनोद वैश्य के संयोजकत्व में सुंदरकांड पाठ, हवन-पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभात साहू ने भगवान शिव एवं हनुमान जी की आराधना कर नगर की शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। प्रभात साहू, प्रथम नागरिक, महराजगंज ने कहा कि, 'नगरवासियों की आस्था और सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि, हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं आज भी समाज को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। भगवान हनुमान एवं भगवान शिव से प्रार्थना है कि नगर में शांति, समृद्धि और विकास का मार्ग सदैव प्रशस्त रहे।

राम जानकी मंदिर के बगल में शराब की दुकान पर उठा विवाद, सनातन धर्म के अपमान का आरोप

● ...अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की चेतावनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार खाला स्थित भव्य राम जानकी मंदिर के समीप संचालित अंग्रेजी शराब एवं बियर मॉडल शॉप को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे सनातन धर्म की आस्था और धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया है। स्वतंत्र प्रभात मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव गोस्वामी ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण, सनातन संस्कृति के उत्थान और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंदिर के ठीक बगल में शराब की दुकान का संचालन गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति सनातन धर्म को अपमानित करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसे जिम्मेदार अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। ऐसे में धार्मिक स्थल के समीप शराब की दुकान होने से न केवल श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक गरिमा भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। गौरव गोस्वामी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मंदिर के समीप स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग

की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन सौंपकर धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले में कार्रवाई की मांग की जाएगी। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच भी इस विषय को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं कि धार्मिक स्थल के समीप संचालित शराब की दुकान के संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है।

योगी सरकार सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सख्त

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार सड़क पर लोगों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और नागरिकों में जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया और महज 7 दिन में बड़े स्तर पर कार्रवाई की। परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान नियमों का पालन न करने पर 20 से 26 मई तक 57,186 चालान किए गए। वहीं 2,669 वाहनों को सीज किया। सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट और सीट बेल्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण इन दोनों बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अभियान के दौरान 23,758 हेलमेट न लगाने वालों के चालान किए गए। इसी तरह 9,083 लोगों के सीट बेल्ट न लगाने पर चालान काटे गए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग दुर्घटना की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। इसको देखते हुए जागरूकता और चेतावनी देने के लिए ड्राइविंग के दौरान मोबाइल उपयोग करने वाले 3,676 लोगों पर कार्रवाई की गई।

संक्षिप्त खबरें

केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 5 से 21 जून तक चलेगा जनकल्याण एवं जनजागरूकता अभियान

प्रयागराज। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद प्रयागराज में 5 जून से 21 जून 2026 तक समेकित जनकल्याण एवं जनजागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी विकास खंडों, नगर निगम एवं नगर निकाय क्षेत्रों में विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की रूपरेखा, कार्यक्रमों की तिथियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सेवा, संस्कार, सुशासन और सम्मान के मूल मंत्र के अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किए।

विश्व पर्यावरण दिवस पर चलेगा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने बताया कि अभियान की शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर होगी। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप जिले के सभी विकास खंडों और नगर निकायों में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा।

14 से 16 जून तक लगेंगे त्रिदिवसीय जनकल्याण मेले

अभियान के तहत 14 से 16 जून तक जिले के सभी विकास खंडों में तीन दिवसीय जनकल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में विभिन्न विभाग अपने-अपने स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देंगे तथा पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण भी करेंगे। मेले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, कौशल विकास सहित अन्य विभागों की योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भी प्रयास किया जाएगा। विकास प्रदर्शनी, प्राकृतिक खेती कार्यशाला और रात्रि चौपाल भी होंगी सीएमओ. ए.के. तिवारी, जिला विकास अधिकारी जी.पी. कुशवाहा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता विकास सेवा संस्थान एवं श्री राम यूथ फाउंडेशन द्वारा राहगीरों श्रमिकों को शरबत वितरण

कानपुर। नौ तपा की भीषण गर्मी के बीच जनता विकास सेवा संस्थान एवं श्री राम यूथ फाउंडेशन द्वारा राहगीरों श्रमिकों को शरबत वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक विधायक अभिजीत सिंह सांगा , अध्यक्ष जितेंद्र सविता व सहयोगी मिंटू सिंह , राघवेंद्र सिंह,विक्रांत शुक्ला, जितेंद्र नंदवंशी, अनिकेत, निशात, विनोद, हर्ष, अभय, अनिमेश कुशवाहा, हरिओम, राजन, छेदा लाल, रुद्र, आशीष, शुभम,मोहित इत्यादि लोग मौजूद रहे।

अधिवक्ता हितों की प्रभावी पैरवी से चैंबर आवंटन की दरों एवं सुरक्षा निधि में ऐतिहासिक संशोधन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दया शंकर त्रिपाठी

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबरों के आवंटन से संबंधित शुल्क एवं सुरक्षा निधि के विषय में अधिवक्ताओं की न्यायोचित चिंताओं को गंभीरता से उठाते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता के नेतृत्व में अधिवक्ता हितों की सशक्त एवं सकारात्मक पैरवी के परिणामस्वरूप चैंबर आवंटन की पूर्व निर्धारित दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एवं चैंबर आवंटन समिति के अध्यक्ष के साथ हुई विस्तृत विचार-विमर्श बैठक तथा बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, सुझावों एवं अधिवक्ता समुदाय की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मासिक किराया एवं सुरक्षा निधि की राशि में उल्लेखनीय कमी किए जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, पूर्व में निर्धारित 2500 एवं 5000 प्रतिमाह के किराए को घटाकर अधिकांश श्रेणियों में 1500 प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा निधि की राशि में भी व्यापक राहत प्रदान करते हुए निर्धारित धनराशि को पर्याप्त रूप से कम किया गया है, जिससे युवा एवं नवोदित अधिवक्ताओं सहित समस्त अधिवक्ता वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि न्यायिक कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। बार एसोसिएशन ने प्रारंभ से ही यह स्पष्ट किया था कि चैंबर आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत एवं अधिवक्ता हितैषी होनी चाहिए तथा किसी भी अधिवक्ता पर अनावश्यक आर्थिक भार नहीं डाला जाना चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद अधिवक्ता समुदाय के अधिकारों, सम्मान एवं कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए विश्वास व्यक्त करता है कि यह निर्णय न्यायालय एवं बार के मध्य सकारात्मक संवाद और समन्वय की उत्कृष्ट परंपरा को और सुदृढ़ करेगा।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी (के.के. द्विवेदी), उपाध्यक्षगण, संयुक्त सचिवगण, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यगण तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की सक्रिय सहभागिता एवं सुझावों ने भी इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बार एसोसिएशन ने इस निर्णय हेतु मुख्य न्यायाधीश एवं चैंबर आवंटन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे अधिवक्ता एकता, संवाद और लोकतांत्रिक प्रयासों की सार्थक सफलता बताया है।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसलाः प्री-कास्ट तकनीक से बनेंगे नाले

दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान होने वाले गंभीर जलभराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू की है। लंबे समय के लिए काम आने के लिए नालों का निर्माण काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पिछले वर्ष घोषित किए गए नए ड्रेनेज मास्टर प्लान को अब युद्धस्तर पर जमीन पर उतारने की तैयारी है। इस योजना के तहत नालों के निर्माण और रीमॉडलिंग कार्य में लगने वाले समय को कम करने के लिए सरकार ने आधुनिक प्री-कास्ट तकनीक को अपनाने का फैसला किया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजधानी के विभिन्न चिन्हित और संवेदनशील जलभराव वाले इलाकों के लिए इस तकनीक से नालों के निर्माण हेतु आधिकारिक तौर पर निविदाएं (टेंडर) जारी कर दी हैं। पारंपरिक निर्माण पद्धतियों (कास्ट -इन-सीटू) को पीछे छोड़ते हुए इस आधुनिक तकनीक के तहत नालों के आकार के कंक्रीट बाक्स पहले ही फैक्टरी या यार्ड में तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद निर्माण स्थल पर केवल जमीन की खुदाई करके इन बाक्सों को आपस में क्रेन की मदद से जोड़ (अलाइन) दिया जाता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक न केवल बेहद टिकाऊ और मजबूत है, बल्कि इससे पानी की निकासी की क्षमता भी बेहतर होती है।

पेंशन सत्यापन में लापरवाही पर 3 अधिकारियों का वेतन रोका गया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मंगलवार को बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विकास भवन सभागार में कल्याणकारी विभागों की पाक्षिक समीक्षा बैठक की। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम करने के सख्त निर्देश दिए।

किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई- पेंशन सत्यापन में लापरवाही मिलने पर तीन अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गयाः 1. रमेश कुमार - जिला समाज कल्याण अधिकारी 2. राजन कुमार - जिला दिव्यांगजन अधिकारी 3. डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन - जिला प्रोबेशन अधिकारी

बैठक की मुख्य बातें- समाज कल्याण विभागः डीएम ने पेंशन सत्यापन और छात्रवृत्ति योजनाओं में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में टेंडर प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागः जिला दिव्यांगजन अधिकारी को सभी पेंशनधारकों का ब्लॉकवार डेटा तैयार करने का निर्देश। अगली बैठक में कुल दिव्यांग पेंशनधारक और पेंशन से वंचित पात्र लोगों की पूरी जानकारी मांगी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभागः मदरसों का 100% सत्यापन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रोबेशन विभागः पेंशन सत्यापन की धीमी गति पर डीएम नाराज हुए। साफ कहा कि पेंशन से जुड़ा कोई भी आवेदन 45 दिन से ज्यादा लंबित न रहे। देरी पर संबंधित तहसीलों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। पिछड़ा वर्ग कल्याणः शादी अनुदान योजना में आवेदन संख्या, स्वीकृत केस और लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट अगली बैठक में देने को कहा गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने दो टूक कहा कि पात्र लाभार्थियों को हर हाल में समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।

हरियाणा से पानी मिलने के बावजूद दिल्ली में जल संकट

दिल्ली। हरियाणा से अधिक पानी मिलने के बाद भी दिल्ली में पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर सामान्य से लगभग साढ़े पांच फीट नीचे चला गया है। इस जलाशय से वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) को कच्चा पानी मिलता है। इसमें कमी आने से दोनों संयंत्र क्षमता के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इस समय राजधानी में लगभग 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) कम पानी की आपूर्ति हो रही है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी पिछले कुछ दिनों से पानी की कमी की बात स्वीकार करते हैं। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लगभग 12 विधानसभा क्षेत्रों से जल आपूर्ति की शिकायत मिल रही है। दिल्ली में लगभग एक हजार एमजीडी पेयजल उपलब्ध होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें कमी आई है। यमुना में पानी की कमी के कारण वजीराबाद जलाशय का जलस्तर 674.15 की जगह 668 फीट रह गया है। वजीराबाद और चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए यमुना से लगभग 135 एमजीडी पानी लिया जाता था। जलाशय का जलस्तर कम होने से इसकी जगह इस समय 50 एमजीडी से भी कम पानी मिल रहा है। इस कारण समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा से कैरियर लिंक कैनाल (सीएलसी) और दिल्ली सब ब्रांच (डीएसबी) नहरों के माध्यम से 920 क्यूसेक पानी मिलता था।

बलियाः बेल्थरा रोड पर किराए के मकान में महिला पर जानलेवा हमला, ईंट से सिर पर वार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बेल्थरा रोड, बलिया - वार्ड नंबर 7 में सोमवार दोपहर एक किराए के मकान में अकेली रह रही महिला पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने घर में घुसकर महिला के सिर पर ईंट से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना का विवरण- पीड़िता की पहचान बिंदु देवी पत्नी प्रणव कुमार यादव के रूप में हुई है। बिंदु देवी ने बताया कि सोमवार दोपहर वह अपने कमरे में अकेली थीं। इसी दौरान एक महिला चार-पांच युवकों के साथ उनके कमरे में घुस आई और बिना किसी बातचीत के हमला कर दिया। हमलावर महिला ने ईंट से उनके सिर पर लगातार वार किए। बिंदु देवी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। मकान मालिक दया शंकर गुप्ता के मौके पर पहुंचने तक सभी हमलावर फरार हो चुके थे।

इलाज और स्थिति- घटना के तुरंत बाद मकान मालिक और मालकिन घायल बिंदु देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार, महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है। पीड़िता ने अपना मूल निवास भेंड़कुल, सुल्तानपुर बताया है। वह बेल्थरा रोड पर किराए के मकान में रह रही थीं।

स्थानीय लोगों में आक्रोश- दिनदहाड़े हुई इस वारदात से वार्ड नंबर 7 और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने घटना पर आक्रोश जताया है। लोगों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और हमले के कारणों का खुलासा करे।

जांच जारी- फिलहाल हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। हमलावर महिला और युवकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सपा का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन

● युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार को कथित पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न तथा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और बाद में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी के झंडे लेकर एकत्र हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बार-बार परीक्षा पत्र लीक होने से लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। युवा वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता न होने के कारण निराश और हताश हैं। सपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता का जीवन कठिन होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर पड़ रहा है, जिससे लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सपा नेताओं ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक चले प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने, महंगाई नियंत्रित करने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

ज्येष्ठ मास के पांचवें मंगलवार पर बड़े हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

● मंगला आरती, अभिषेक और भव्य श्रृंगार के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन; शाम को लगेगा छप्पन भोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में ज्येष्ठ मास के पांचवें मंगलवार को बंधवा स्थित प्रसिद्ध लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। तड़के भोर से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। बजरंगबली के दर्शन और पूजन के लिए प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिरस, भजन-कीर्तन और जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। मंगलवार सुबह मंगला आरती से पूर्व मंदिर के महंत बलबीर गिरी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़े हनुमान जी का विधि-विधान से अभिषेक कराया। अभिषेक में गंगाजल, दूध, शहद, हल्दी तथा अन्य पवित्र सामग्री का उपयोग किया गया। इसके बाद भगवान को विशेष वस्त्र, पुष्प, फल, मेवा और सुगंधित सामग्री अर्पित कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। अभिषेक और श्रृंगार के पश्चात घंट-घड़ियाल, शंख और नगाड़ों की मंगल ध्वनि के बीच मंगला आरती संपन्न हुई। आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया था, जिसने श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित किया।

भोर से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें

ज्येष्ठ मास के विशेष मंगलवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा दर्शन-पूजन की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बड़े हनुमान जी के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि तथा मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की।

ज्येष्ठ मंगलवार का विशेष धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार भगवान हनुमान की आराधना के लिए अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से भय, रोग, संकट तथा नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों का विश्वास है कि बड़े हनुमान जी के दर्शन से आरोग्य, सुख-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ से गूंजा परिसर

मंदिर परिसर में सुबह से ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन निरंतर चलता रहा। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पाठ में भाग लिया और बजरंगबली के चरणों में मत्था टेककर अपने परिवार की खुशहाली, निरोग जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा।

शाम को लगेगा विशेष छप्पन भोग

मंदिर प्रशासन के अनुसार दर्शन-पूजन का क्रम देर रात तक जारी रहेगा। शाम को बड़े हनुमान जी को विशेष छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ज्येष्ठ मास के पांचवें मंगलवार पर बड़े हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धा और भक्ति की यह अद्भुत छटा प्रयागराज की धार्मिक परंपराओं और सनातन आस्था की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती रही। पूरे दिन मंदिर परिसर 'जय श्रीराम' और 'बोलो पवनपुत्र हनुमान की जय' के जयकारों से गूंजता रहा।

IPL 2026 के मैचों से लखनऊ पुलिस को मिला 7.25 करोड़ राजस्व, अब आयोजकों से वसूला जाएगा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। वर्ष 2026 में हुए साथ आईपीएल मैच से लखनऊ पुलिस को 7.25 करोड़ रुपये मिले हैं। यह शुल्क नए नियम के हिसाब से लिए गए हैं। ऐसे तो हर प्राइवेट कार्यक्रम में तैनात प्रति पुलिसकर्मी का शुल्क जोड़कर लिया जाता था, लेकिन शासन की तरफ से सभी मैच के फीस तय कर दी है। इकाना स्टेडियम में आयोजित होने वाले टी-20, आईपीएल और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नया बंदोबस्त शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। अब इन मैचों के दौरान स्टेडियम के भीतर और बाहर तैनात किए जाने वाले पुलिस, पीएसी और होमगार्ड बल पर होने वाला खर्च आयोजकों से लिया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार टी-20 अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के लिए प्रति मैच 25 लाख रुपये का बंदोबस्त शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए यह शुल्क 50 लाख रुपये तय किया गया है। यह राशि सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय के मद्देनजर वसूली जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शुल्क में स्टेडियम की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों शामिल रहेंगी। मैच के दौरान किसी विशेष खतरे या सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकेगा। हालांकि यह अतिरिक्त शुल्क मूल पुलिस निपटान शुल्क के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त शुल्क लगाने से पहले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही अतिरिक्त वित्तीय भार लगाया जाए। यही नहीं मैचों से प्राप्त होने वाला बंदोबस्त शुल्क को जमा कराया जाएगा। आदेश में लखनऊ के अलावा कानपुर और वाराणसी को भी शामिल किया गया है। वहां के पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में आयोजित होने वाले टी-20, आईपीएल और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए निर्धारित शुल्क नियमानुसार वसूल कर संबंधित लेखाशीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

दो जून की रोटी : संघर्ष, सम्मान और समाज की जिम्मेदारी - सरस सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। 'दो जून की रोटी '– यह केवल एक मुहावरा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे 'दो जून की रोटी' कमानी है, तो उसके पीछे सिर्फ भोजन की जरूरत नहीं, बल्कि पूरे परिवार के अस्तित्व, सम्मान और भविष्य की चिंता छिपी होती है। भारत गांवों का देश है। यहां खेतों में पसीना बहाने वाला किसान, सड़क किनारे रिक्शा चलाने वाला मजदूर, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाली महिलाएं, निर्माण स्थलों पर दिन-रात मेहनत करने वाले श्रमिक और छोटे दुकानदार सभी का संघर्ष कहीं न कहीं दो जून की रोटी से जुड़ा है। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलना और शाम को थके कदमों से लौटना, उनके जीवन की रोजमर्रा की कहानी है। आज विज्ञान और तकनीक के इस आधुनिक युग में जहां एक ओर देश चांद और मंगल तक पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी पेट भरने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की असमानता ने गरीब और मध्यम वर्ग की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए दो वक्त का भोजन जुटाना भी किसी युद्ध जीतने से कम नहीं। दो जून की रोटी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जब कोई बच्चा भूखे पेट सोता है, तो यह केवल उसके परिवार की विफलता नहीं होती, बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था के लिए चिंता का विषय होता है। भूख इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है और जब पेट खाली होता है तो सपने, शिक्षा और विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं। हालांकि सरकारों द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राशन वितरण, मनरेगा, गरीब कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लाखों लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हर व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार और पर्याप्त आय उपलब्ध नहीं होगी, तब तक दो जून की रोटी का संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकेगा। समाज के सक्षम वर्ग की भी जिम्मेदारी है कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। किसी भूखे को भोजन कराना केवल दान नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। हमें यह समझना होगा कि किसी की थाली में भोजन पहुंचाना, उसके जीवन में उम्मीद पहुंचाने जैसा है। दो जून की रोटी की अहमियत वही समझ सकता है जिसने भूख की पीड़ा महसूस की हो। जिन लोगों के घरों में भोजन आसानी से उपलब्ध है, उन्हें कभी उन हाथों को भी देखना चाहिए जो दिनभर मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते। यह संवेदनशीलता ही एक बेहतर समाज की पहचान है। अंततः, दो जून की रोटी केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि इंसान के सम्मान, आत्मनिर्भरता और जीवन के अधिकार का प्रतीक है।

साउथ मलाका में एक ही परिवार के चार शव मिलने से सनसनी

● बंद मकान से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, हत्या की आशंका; पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका इलाके में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव उनके बंद मकान से बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कई दिनों से घर से आ रही तेज दुर्गंध के बाद पड़ोसियों द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलग-अलग कमरों में चार शव पड़े मिले। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय व्यवसायी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता वैश्य (65 वर्ष), पुत्री मीनाक्षी वैश्य (45 वर्ष) तथा पुत्र अभिषेक वैश्य के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में शव लगभग तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं।

दुर्गंध से हुई अनहोनी की आशंका

स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। मंगलवार को मकान से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मकान का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो चारों ओर सन्नाटा पसरा था और परिवार के चारों सदस्य मृत अवस्था में मिले।

शवों पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। घटनास्थल की स्थिति और मिले साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। घर के भीतर और आसपास के क्षेत्र की भी जांच की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना से जुड़े किसी सुराग तक पहुंचा जा सके।

इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल

एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर फैलते ही साउथ मलाका समेत पूरे शहर में चर्चा का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल के बाहर एकत्र हो गए। लोगों में घटना को लेकर भय और चिंता का माहौल है।

पुलिस ने कहा—हर बिंदु पर हो रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। हत्या, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद अथवा अन्य कारणों को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। यह हृदयविदारक घटना पूरे प्रयागराज में चर्चा का विषय बनी हुई है।

प्रयागराज निवासियों का कहना है कि एक परिवार के सभी चार लोगों की हत्या से प्रयागराज की पुलिस व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पुलिश रात में पेट्रोलिंग कहा करती है गश्त कहा लगती है अधिकारियों का रात में कहा और किस क्षेत्र में आवा गमन रहता है तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे है जो पुलिश की पुलिसिंग व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहा है। जब की प्रयागराज पुलि स कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत आता है जहां सभी अधिकारी ips रैंक के तैनात है और तेजतर्रआक माने जाते है।